CEASI TIMES

24th June 2025

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्क्फोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क् का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- **15+ राज्य**
- **15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया**
- **20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया**
- **5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया**
- **3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया**
- **30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया**

आंध्र प्रदेश में 25,000 से ज्यादा छोटे किसानों को खेती के औज़ार दिए गए

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024–25 की फार्म मैकेनाइजेशन योजना के तहत 25,192 छोटे और सीमांत किसानों को ₹60.53 करोड़ के खेती के औज़ार दिए। किसानों को इन उपकरणों पर 50% की सब्सिडी दी गई है, जिससे खेती आसान और लाभदायक हो सके।

इस योजना की शुरुआत अमरावती में कृषि निदेशक दिल्ली राव ने की। उपकरणों का वितरण कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया। किसानों का चयन करषक पोर्टल के माध्यम से हुआ, और उनकी ज़मीन व फसल की जानकारी डिजिटल माध्यमों से जांची गई। आदिवासी किसानों की पुष्टि गिरी भूमि पोर्टल से की गई।

जिलों में कलेक्टरों की निगरानी में स्थानीय रैतु सेवा केंद्रों (RSKs) पर उपकरण दिए गए। पारदर्शिता के लिए लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की गई।

निदेशक राव ने कहा कि यह योजना छोटे किसानों को आधुनिक उपकरण अपनाने में मदद करेगी और उनकी आमदनी बढ़ाएगी। यह राज्य की कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

भारत अब खेती के औज़ारों का निर्यात करेगा, छोटे किसानों और नवाचार पर ज़ोर

भारत अब खेती के औज़ारों के निर्माण में एक वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पंजाब दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अब न सिर्फ़ अपने किसानों के लिए कृषि यंत्र बनाएगा, बल्कि इन्हें दुनिया के अन्य देशों को भी निर्यात करेगा।

उन्होंने अमरगढ़ में एक आधुनिक कृषि उपकरण फैक्ट्री का दौरा किया और स्थानीय फसलों की स्थिति की समीक्षा की। मंत्री ने मल्टीपर्पज़ हार्वेस्टर, ट्रांसप्लांटर और कम लागत वाले उपकरणों के निर्माण की सराहना की, जो खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपयोगी हैं।

उन्होंने कहा कि ये औज़ार सस्ते होने चाहिए और भारतीय खेती की ज़रूरतों के अनुसार बनाए जाने चाहिए। सब्सिडी सिर्फ़ असली किसानों को मिले और आधुनिक उपकरण लागत घटाने, मेहनत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायक हों।

उन्होंने वैज्ञानिकों से जलवायु सहनशील बीज विकसित करने का आग्रह किया। जल्द ही एक राष्ट्रीय यंत्रीकरण योजना लाई जाएगी, जिसमें किसानों की ज़रूरतें प्राथमिकता होंगी।

भारत-यूक्रेन की पहली कृषि बैठक, यंत्रीकरण और डिजिटल खेती पर हुआ ज़ोर

भारत और यूक्रेन ने 18 जून को अपनी पहली संयुक्त कार्यसमूह (Joint Working Group) बैठक वर्चुअल माध्यम से की। बैठक का उद्देश्य खेती में तकनीक और ज्ञान साझा कर दोनों देशों की कृषि को आधुनिक बनाना था।

बैठक में खेती के यंत्रीकरण, डिजिटल कृषि, जलवायु अनुकूल खेती और मिट्टी की सेहत जैसे विषयों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने किसानों के लिए स्मार्ट समाधान विकसित करने पर सहमति जताई, जैसे फसल योजना, मौसम पूर्वानुमान और बाजार तक पहुंच के लिए डिजिटल टूल्स।

भारत ने ई-नाम (e-NAM) जैसे प्लेटफ़ॉर्म और आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को लेकर अपनी उपलब्धियाँ साझा कीं। यूक्रेन ने खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उपकरण और पौध प्रजनन तकनीकों में सहयोग की रुचि दिखाई।

अधिकारियों ने इसे तकनीक आधारित खेती के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत बताया। दोनों पक्षों ने मिलकर किसानों के लिए नई पहलें शुरू करने और संवाद जारी रखने पर सहमति दी।

यह साझेदारी खेती को कुशल, आधुनिक और जलवायु के अनुकूल बनाने में सहायक होगी।

उत्तर प्रदेश में ड्रोन से खेती को नई उड़ान, 1 घंटे में 12 एकड़ में छिड़काव संभव

उत्तर प्रदेश में खेती को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन तकनीक की शुरुआत की गई है। अब नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से किया जा रहा है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है।

लखनऊ, गोरखपुर, बहराइच, मुज़फ्फरनगर, गाज़ियाबाद और कानपुर नगर में यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। एक ड्रोन एक घंटे में 3 से 12 एकड़ तक फसल पर छिड़काव कर सकता है। यह पहल आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना और कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत चलाई जा रही है।

अब तक 9 ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, और किसानों को ड्रोन चलाने व आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे फसलों की देखभाल समय पर और सटीक हो रही है, जिससे नुकसान कम होगा और उपज बढ़ेगी।

यह तकनीकी पहल खेती को स्मार्ट बना रही है और किसानों को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। जल्द ही यह योजना अन्य ज़िलों में भी फैलाई जाएगी।

तेलंगाना बागवानी विश्वविद्यालय और कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच समझौता, छात्र आदान-प्रदान और शोध सहयोग पर जोर

तेलंगाना बागवानी विश्वविद्यालय ने अमेरिका की कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालयों के छात्र शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे और बागवानी अनुसंधान में वैश्विक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे।

समझौते में संयुक्त अनुसंधान और खेत-स्तरीय परियोजनाओं पर भी विशेष बल दिया गया है, जिससे राज्य के किसानों की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समाधान विकसित किए जा सकें। यह सहयोग स्थानीय कृषि समस्याओं के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने का अवसर देगा। यह पहल ज्ञान हस्तांतरण, क्षमतावर्धन और नवाचार को बढ़ावा देकर बागवानी क्षेत्र में व्यावहारिक सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

कर्नाटक से पहली बार ताज़ा जामुन का निर्यात ब्रिटेन को, भारतीय बागवानी क्षेत्र के लिए मील का पत्थर

भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने कर्नाटक से पहली बार ताज़ा जामुन फल (कुंदना किस्म) का निर्यात यूनाइटेड किंगडम को सफलतापूर्वक कराया। यह जामुन सीधे एक किसान उत्पादक संगठन (FPO) से खरीदा गया, जिससे किसानों को स्थानीय बाजार मूल्य (₹50–60 प्रति किलो) की तुलना में लगभग दोगुनी आय (₹110 प्रति किलो) प्राप्त हुई। यह कदम भारतीय पारंपरिक फलों को वैश्विक बाजार में स्थान दिलाने के साथ-साथ किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

जामुन की पैकिंग और प्रोसेसिंग एक अत्याधुनिक संयंत्र में की गई, जिसे APEDA और प्लांट क्वारंटाइन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था और कर्नाटक के उद्यान विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। अब तक जामुन का निर्यात केवल प्रोसेस्ड या बीज पाउडर रूप में होता था, जबकि यह पहली बार है जब पूरा ताज़ा फल निर्यात किया गया है। कर्नाटक, एक प्रमुख जामुन उत्पादक राज्य के रूप में, ताज़ा फलों के निर्यात का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। APEDA ऐसे प्रयासों को GI और ODOP जैसी योजनाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे रहा है।

कर्नाटक में 49,500 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती मिशन लागू होगा

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत भारत सरकार ने पारंपरिक और रसायन-मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल की है। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक में इस वर्ष 49,500 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाई जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों का 60:40 अनुपात में वित्तीय सहयोग रहेगा। यह मॉडल मिट्टी, जल, सूक्ष्मजीव, पौधों, पशुओं और जलवायु आधारित पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित है, जिसमें केवल स्थानीय रूप से उपलब्ध जैविक इनपुट का उपयोग किया जाएगा।

राज्य में लगभग 900 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं, प्रत्येक में लगभग 125 किसान शामिल होंगे और हर किसान अधिकतम एक एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करेगा। हर क्लस्टर में दो कृषि सखी मार्गदर्शन प्रदान करेंगी और प्रत्येक तीन क्लस्टरों पर एक जैविक इनपुट संसाधन केंद्र (BRC) स्थापित किया जाएगा। तटीय कर्नाटक के उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में 1,550 हेक्टेयर क्षेत्र में यह पहल लागू होगी। चयनित कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण एवं निगरानी की जाएगी। यह योजना कृषि और बागवानी की कई फसलों पर लागू होगी।

अमरावती क्षेत्र के ईडब्ल्यूएस युवाओं के लिए उद्यान कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

वेलगापुडी स्थित सचिवालय के पास एपीसीआरडीए नर्सरी में तीन सप्ताह का माली प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अमरावती राजधानी क्षेत्र के गांवों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और बेरोजगार युवाओं को उद्यान संबंधी कौशल प्रदान करना है। यह कार्यक्रम एपीसीआरडीए, बागवानी विभाग और एडीसीएल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के 30 चयनित प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का संचालन बागवानी विभाग के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है, जबकि एपीसीआरडीए द्वारा प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधा और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया गया है।

प्रशिक्षण के पश्चात प्रतिभागियों को उनकी योग्यता और परियोजना की मांग के अनुसार एडीसीएल द्वारा संचालित हरित और परिदृश्य विकास परियोजनाओं में कार्य का अवसर प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत उड्डंडरायुनिपालेम में एक स्थायी बागवानी नर्सरी एवं प्रशिक्षण केंद्र (HNTC) स्थापित करने की योजना भी घोषित की गई, जो भविष्य में बागवानी क्षेत्र में निरंतर क्षमता विकास का क्षेत्रीय केंद्र बनेगा। यह पहल शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में युवाओं के लिए आजीविका सृजन का एक महत्वपूर्ण कदम है।

महाराष्ट्र से अंगूर, संतरा और अनार के लि 'क्लीन प्लांट प्रोग्राम' की शुरुआत

केंद्र सरकार ने अंगूर, संतरा और अनार की फसलों के लिए रोग-मुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 'क्लीन प्लांट प्रोग्राम' की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की जा रही है। यह राष्ट्रव्यापी पहल पुणे में आयोजित भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय एग्री हैकाथॉन के दौरान घोषित की गई। यह कार्यक्रम बागवानी क्षेत्र में उत्पादक और रोग-मुक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। देशभर में नौ 'क्लीन प्लांट सेंटर' स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से तीन महाराष्ट्र में पुणे (अंगूर), नागपुर (संतरा) और सोलापुर (अनार) में ₹300 करोड़ के निवेश के साथ स्थापित किए जाएंगे।

इन परियोजनाओं के तहत आधुनिक नर्सरियों की स्थापना भी की जाएगी, जो तकनीक आधारित कृषि को समर्थन देंगी। बड़ी नर्सरियों को ₹3 करोड़ और मध्यम आकार की नर्सरियों को ₹1.5 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे प्रतिवर्ष आठ करोड़ रोग-मुक्त पौध तैयार होंगे। इस पहल के तहत इज़राइल और नीदरलैंड जैसे देशों से सहयोग की योजना भी है। 'लैब टू लैंड' रणनीति के अंतर्गत 16,000 वैज्ञानिकों को किसानों के साथ सीधा जुड़ाव करने के लिए तैनात किया जाएगा, जिससे अनुसंधान और खेत स्तर पर उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। यह कार्यक्रम बागवानी क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता को नया आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आंध्र प्रदेश सरकार बागवानी किसानों को राहत देने के लिए उठाएगी ठोस कदम

आंध्र प्रदेश सरकार ने तंबाकू, आम और कोको जैसी प्रमुख फसलों की खरीद और मूल्य निर्धारण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई रणनीतिक पहल की हैं। किसान-केन्द्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण कर समस्याओं की पहचान करने और उत्पादन में वैश्विक मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोको की गुणवत्ता बढ़ाने और किसानों में जागरूकता लाने के लिए एक समर्पित नीति लाई जाएगी। साथ ही, कृषक उत्पादक संगठन (FPO) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रसंस्करण क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु सहायता दी जाएगी।

तंबाकू क्षेत्र में, फ्लू-क्योरड वर्जीनिया (FCV) खेती को नियंत्रित किया जाएगा जबकि व्हाइट बर्ले तंबाकू अनुबंध खेती के माध्यम से उत्पादित होगी। सात प्रमुख मंडियों से 2.5 करोड़ किलोग्राम तंबाकू की खरीद की जाएगी। आम के क्षेत्र में कम मांग के चलते सरकार किसानों को ₹8 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीद होने की स्थिति में ₹4 प्रति किलोग्राम का मुआवजा देगी। कोको के लिए ₹500 न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने हेतु ₹50 की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, 116 से बढ़ाकर 200 रैतु बाजारों की स्थापना, मोबाइल मार्केट और पीएम-किसान से जुड़ा किसान डेटाबेस विकसित किया जाएगा।

पशुपालन विभाग और FAO ने 'वन हेल्थ' कार्यशाला आयोजित की, पशु स्वास्थ्य संचार को बढ़ावा देने पर जोर

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के सहयोग से नई दिल्ली में एक 'वन हेल्थ संचार रणनीति कार्यशाला' का आयोजन किया। यह कार्यशाला "पैंडेमिक फंड" द्वारा समर्थित परियोजना "भारत में महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण" के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के केंद्र में रखकर संचार को मजबूत करना और देश की पशु स्वास्थ्य प्रणाली और महामारी से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करना था।

इस कार्यक्रम में सरकार, अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य फोकस ज़ूनोटिक बीमारियों, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR), और जैव सुरक्षा पर था, जिसमें विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर प्रभावी संदेश पहुँचाने पर बल दिया गया।

पशुपालन आयुक्त डॉ. अभिजीत मित्रा ने सरल और स्थानीय भाषा में संचार के महत्व पर ज़ोर दिया, जबकि FAO के डॉ. कोंडा चव्वा ने संचार को "ज्ञान और व्यवहार के बीच की कड़ी" बताया। बीबीसी न्यूज़ सहित वरिष्ठ पत्रकारों की भागीदारी से मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में जोखिम संचार और अंतर-विभागीय समन्वय पर तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए।

सेलम में आधुनिक दुग्ध उत्पादन तकनीकों पर सेमिनार आयोजित

सेलम के अलागापुरम स्थित को-ऑपरेटिव बैंक कम्युनिटी हॉल में आधुनिक दुग्ध उत्पादन तकनीकों पर एक जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाना और डेयरी किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना था। इस अवसर पर ₹5.34 करोड़ की कल्याणकारी सहायता 1,787 लाभार्थियों को वितरित की गई।

सेमिनार में सेलम जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (Aavin) की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। वर्तमान में, यह 784 सहकारी समितियों के माध्यम से 2.24 लाख सदस्यों को जोड़ चुका है। 46,947 दुग्ध उत्पादकों से प्रतिदिन औसतन 6.35 लाख लीटर दूध की खरीद की जा रही है। सेलम स्थित Aavin संयंत्र की क्षमता पांच लाख लीटर प्रतिदिन है, जबकि अत्तूर में 1.30 लाख लीटर की क्षमता वाला चिलिंग सेंटर और जिले में 104 बल्क मिल्क कूलर कार्यरत हैं।

Aavin की आइसक्रीम उत्पादन इकाई 6,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ सेलम व आस-पास के क्षेत्रों में आपूर्ति करती है। सेमिनार में दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए। अधिकारियों ने सात लाख लीटर क्षमता वाले ऑटोमेटेड दूध प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण भी किया।

अंडमान में मुंह और खुर रोग टीकाकरण अभियान के तहत 5,500 से अधिक मवेशियों को लगाया गया टीका

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा दक्षिण अंडमान में मुंह और खुर रोग (FMD) के खिलाफ एक व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 2 जून 2025 को शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 5,506 मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि महीने के अंत तक 9,000 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।

जानवरों पर तनाव कम करने के लिए टीकाकरण कार्य दिन के ठंडे समय में किया जा रहा है। 11 पशु चिकित्सकीय टीमें—जैसे VH जंगलीघाट, VH गरचरमा, VD रंगाचंग, VD मंगलुतान आदि—हर दिन 300–400 पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं, वह भी मानसून की कठिन परिस्थितियों में।

FMD एक अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है, जिससे बुखार, पैरों और मुंह में छाले, लंगड़ापन और दूध उत्पादन में 30% तक गिरावट होती है। टीकाकरण किए गए पशुओं को टैग किया जाता है और उनकी जानकारी भारत पशुधन पोर्टल पर वास्तविक समय में अपलोड की जाती है। विभाग ने सभी पशुपालकों से टीमों के साथ सहयोग करने की अपील की है ताकि समय पर टीकाकरण सुनिश्चित हो सके और रोग का प्रसार रोका जा सके।

मध्य प्रदेश में गौशालाओं को ₹90 करोड़ की सहायता, डेयरी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावाt

मध्य प्रदेश में हाल ही में आयोजित एक राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और पशु कल्याण सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इस अवसर पर राज्य भर की गौशालाओं को ₹90 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे गौवंश की देखभाल और प्रबंधन में सुधार हो सके।

गौशालाओं के लिए प्रति गाय प्रतिदिन दी जाने वाली सहायता राशि ₹20 से बढ़ाकर ₹40 कर दी गई है। इसके साथ ही, दुग्ध सहकारी समितियों (समितियों) की संख्या 9,000 से बढ़ाकर 26,000 करने की योजना है, ताकि दूध उत्पादन और संग्रहण को अधिक संगठित किया जा सके। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ दुग्ध उत्पादन को पांच गुना बढ़ाने के लिए एक समझौता भी किया गया है।

गौशालाओं के निर्माण हेतु 125 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। भोपाल, दमोह, अनुपपुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, हरदा और विदिशा की सात उत्कृष्ट गौशालाओं को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, हर गांव में 'वृंदावन गांव' की स्थापना की योजना है, जिससे बच्चों को पौष्टिक दूध उपलब्ध हो सके और घायल व बेसहारा मवेशियों को आश्रय मिल सके।

खाद्य सुरक्षा की कीमत पर ईंधन टिकाऊ नहीं: जैव ईंधन पर विशेषज्ञों की चेतावनी

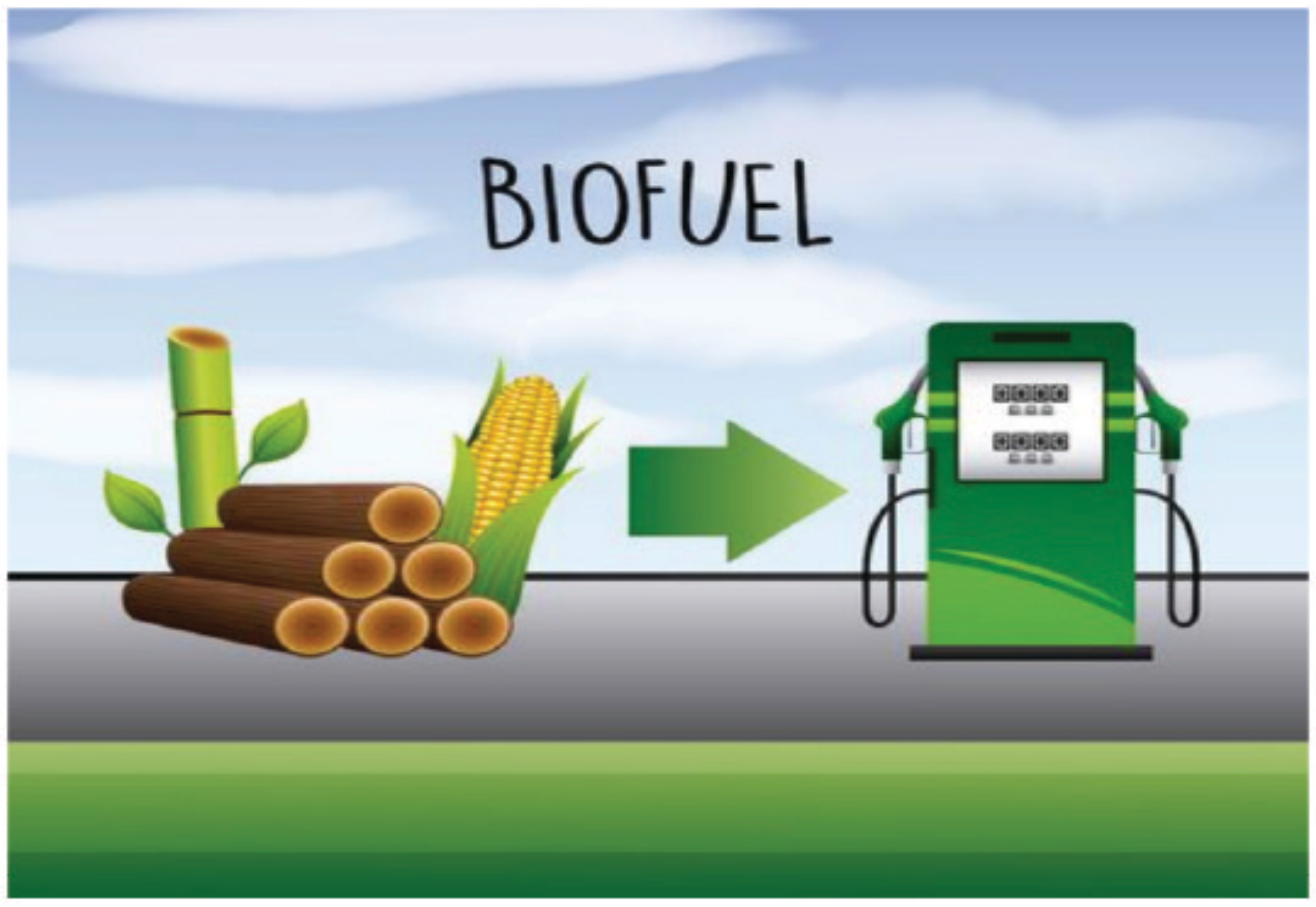

भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के तहत जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की योजना ने खाद्य सुरक्षा और संसाधन आवंटन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। 2029-30 तक 2.2 एक्साजूल (EJ) जैव ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बायोएथेनॉल, बायोगैस, बायोडीजल, बायो-पैलेट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और बायो-मेथनॉल जैसे सात ईंधन शामिल हैं।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि खाद्य फसलों और सार्वजनिक अनाज भंडार को ईंधन के लिए मोड़ा जा रहा है। 2025-26 तक के एथेनॉल लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में गन्ना, मक्का और चावल की आवश्यकता होगी, जिससे खाद्य आपूर्ति और पशु आहार प्रभावित हो सकते हैं। अनुमान है कि इसके लिए 70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की आवश्यकता होगी।

2024-25 में 52 लाख टन चावल को सब्सिडी दर पर एथेनॉल उत्पादन के लिए बेचा गया, जो उत्पादन लागत से काफी कम था। इसके अतिरिक्त, एथेनॉल के उप-उत्पाद DDGS ने सोयाबीन आहार की कीमतें गिरा दी हैं, जिससे किसान आय और घरेलू तेल उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपशिष्ट-आधारित जैव ईंधनों की ओर रुख करना चाहिए और ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो पोषण सुरक्षा, किसान आय और ग्रामीण आजीविका को प्रभावित किए बिना ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करें।

महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र के लिए एआई नीति को मंजूरी, डेटा एकीकरण और रियल-टाइम समर्थन पर जोर

महाराष्ट्र कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'महा एग्री - एआई नीति 2025–29' को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य कृषि डेटा सेट्स, भू-स्थानिक जानकारी, खाद्य सुरक्षा का मानकीकरण और किसानों को रियल-टाइम मार्गदर्शन तथा जरूरी सूचनाएं प्रदान करना है। इसके तहत एक 'एग्रो डेटा एक्सचेंज (A-DeX)' प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, जो सरकार के एग्रीस्टैक, महा एग्रीटेक, महावेद और भंडारण से जुड़े डेटा को निजी स्रोतों जैसे बाजार जानकारी, सैटेलाइट डेटा, जलवायु विश्लेषण, आपूर्ति श्रृंखला आदि से जोड़ेगा। इस प्रणाली में स्टार्टअप्स, उद्योग, किसान उत्पादक संगठन, अनुसंधान संस्थान और सरकारी विभाग भी शामिल होंगे।

एआई-आधारित कृषि परियोजनाओं का प्राथमिक मूल्यांकन 'एग्रीएआई सेल' द्वारा किया जाएगा, और फिर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति इनकी व्यवहार्यता और वित्तीय सहायता पर निर्णय लेगी। 'महा विस्तार एआई' नामक एक ओपन नेटवर्क पोर्टल, चैटबॉट और आईवीआरएस जैसे डिजिटल माध्यमों से कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैकाथॉन जैसे प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। नीति के पहले तीन वर्षों के लिए सरकार ने ₹500 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' घोषित किया न्यूयॉर्क, 18 जून 2025:

संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' घोषित किया है। यह फैसला दुनिया भर में कृषि और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की अहम भूमिका को सम्मान देने के लिए लिया गया है।

महिला किसान विश्व स्तर पर लगभग 50% खाद्य उत्पादन में योगदान देती हैं। विकासशील देशों में यह आंकड़ा 60–80% तक जाता है। इसके बावजूद उन्हें भूमि, ऋण, तकनीक और प्रशिक्षण तक सीमित पहुंच जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इस पहल का उद्देश्य महिला किसानों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना, उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना और महिला-नेतृत्व वाले कृषि बाजारों को मज़बूत करना है।

यह कदम जलवायु-लचीली खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका सुधारने में भी मदद करेगा।

भारत में 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना' और असम का मोबाइल-आधारित जलवायु परामर्श जैसे कार्यक्रम पहले से महिलाओं को सक्षम बना रहे हैं।

साल 2026 महिला किसानों के योगदान को पहचानने, सहयोग देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का वर्ष होगा।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि पर जोर

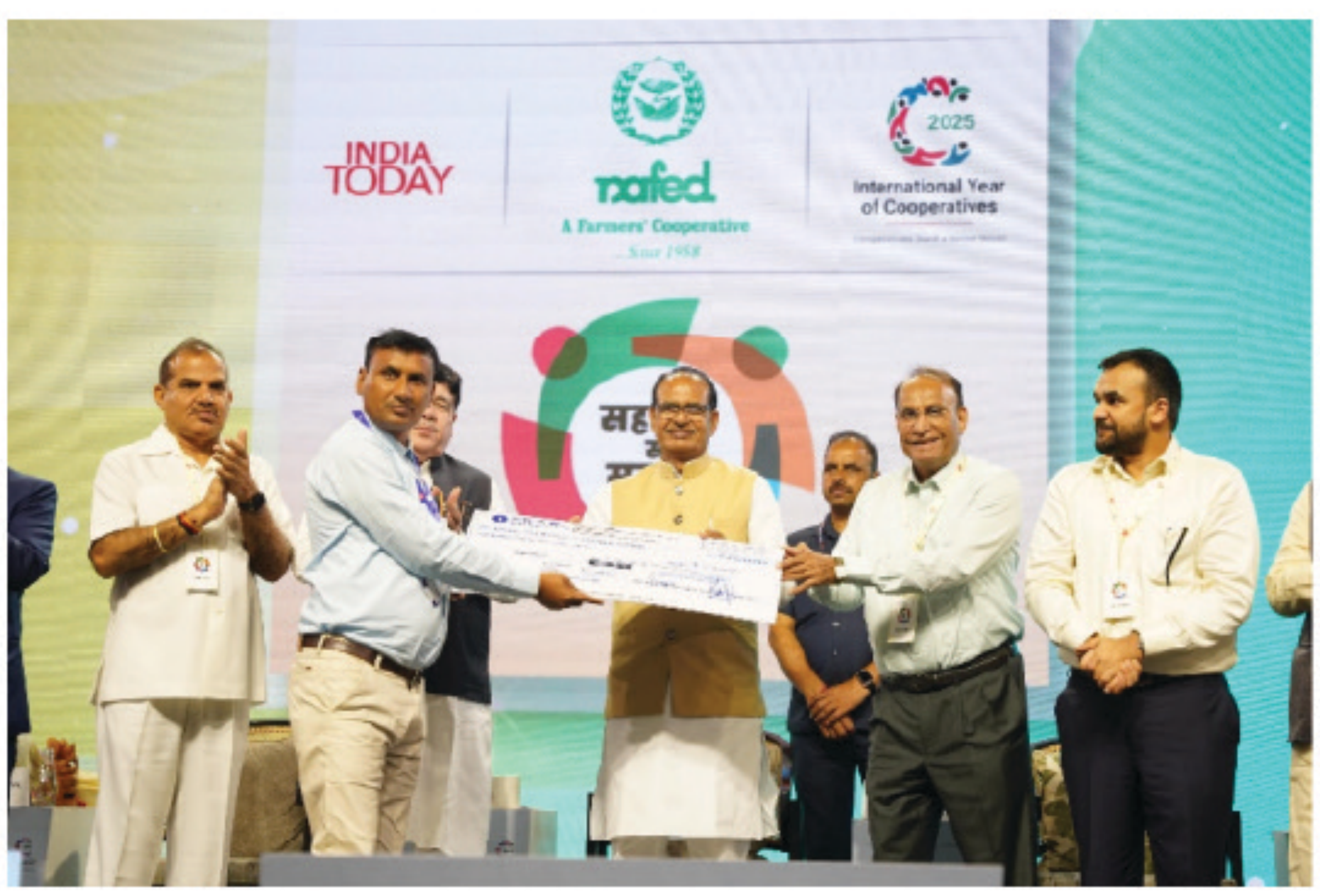

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में "सहकारिता से समृद्धि" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने के उपलक्ष्य में किया गया था। उन्होंने कहा कि सहकारिता भारत की कृषि परंपरा की जड़ में है और ग्रामीण विकास का मजबूत आधार है।

मंत्री ने छोटे किसानों के लिए समेकित खेती मॉडल, वैज्ञानिक तरीकों और उचित बाजार मूल्य की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने "लैब से ज़मीन तक" की नीति को ज़रूरी बताया, जिसके तहत वैज्ञानिक खेतों में जाकर किसानों से जुड़ रहे हैं।

उन्होंने ड्रोन तकनीक, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और टमाटर, प्याज, आलू जैसी फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) की भी जानकारी दी। खराब बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम में NAFED द्वारा समर्थित सफल एफपीओ को सम्मानित किया गया और इक्विटी अनुदान वितरित किए गए। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे किसानों को तकनीक और सहयोग के ज़रिए सशक्त बनाना रहा।

विजयवाड़ा ग्रामीण में सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट-रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा

20 जून 2025 को सीईएएसआई (CEASI) ने सोमपो जनरल इंश्योरेंस (Sompo General Insurance) के सहयोग से तुन्ना गांव, विजयवाड़ा ग्रामीण, आंध्र प्रदेश में सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट-रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर एक दिवसीय अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया।

यह प्रोग्राम किसानों को सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेज़ और क्लाइमेट-रिलेटेड रिस्क्स से निपटने की जानकारी देने की एक श्रृंखला की शुरुआत था। इस सेशन में 50 से अधिक किसान शामिल हुए, जहां सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, वॉटर कंज़र्वेशन, क्लाइमेट-रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज़, और इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

इस प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण क्रॉप इंश्योरेंस पर दिया गया जोर था। सोमपो जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों ने किसानों को बताया कि वे एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण होने वाले क्रॉप लॉस से अपनी आजीविका कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और साथ ही उन्होंने बीमा योजनाओं और एनरोलमेंट प्रोसेस की जानकारी भी दी।

यह प्रोग्राम इंटरऐक्टिव, जानकारीपूर्ण और किसानों द्वारा सराहा गया। यह CEASI और सोमपो जनरल इंश्योरेंस की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वे ग्रामीण समुदायों को अवेयरनेस, एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से सशक्त बनाना चाहते हैं।

प्रोग्राम के अंत में सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए।

यह पहल भविष्य में ऐसे और प्रयासों की नींव रखती है, जो किसानों को सशक्त बनाएंगे और लॉन्ग-टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देंगे।

अयोध्या में फार्मर्स को एमपावर करना: सस्टेनेबल शुगरकेन कल्टीवेशन को बढ़ावा

सश्वत मिठास इनिशिएटिव के तहत, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया द्वारा UPL SAS लिमिटेड के साथ साझेदारी में सस्टेनेबल शुगरकेन फार्मिंग प्रैक्टिसेज़ को अयोध्या में प्रमोट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य फार्मर्स की क्षमता को ईको-फ्रेंडली कल्टीवेशन मेथड्स के माध्यम से बढ़ाना है, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हुए एनवायर्नमेंटल रिसोर्सेज़ को भी प्रिज़र्व करें।

एक डेडिकेटेड टीम मौजूदा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ को समझने और इंप्रूवमेंट के ऑपर्च्युनिटीज़ को पहचानने के लिए एक्स्टेंसिव फील्ड सर्वे कर रही है। प्रैक्टिकल लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए, डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट्स ग्रासरूट लेवल पर बनाए जा रहे हैं। ये प्लॉट्स सस्टेनेबल शुगरकेन कल्टीवेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ दिखाते हैं, जैसे एफिशिएंट वॉटर मैनेजमेंट, सॉयल हेल्थ रेस्टोरेशन, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग।

नॉलेज डिसेमिनेशन को प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के साथ जोड़कर, यह प्रोजेक्ट फार्मर्स को क्लाइमेट-रेजिलिएंट और एनवायर्नमेंटली रिस्पॉन्सिबल एप्रोच अपनाने के लिए मोटिवेट करता है। इस इनिशिएटिव का लक्ष्य केवल क्रॉप यील्ड बढ़ाना नहीं है, बल्कि लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी और रीजन के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में इकोलॉजिकल बैलेंस सुनिश्चित करना भी है।

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india